



2026:AHC:54971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10798/2026

स्नेहलता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता: नरेन्द्र कुमार

विपक्षी दल के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर सरकारी अधिवक्ता) को सुना गया।
2. यह आवेदन आवेदक द्वारा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 4, मैनपुरी द्वारा शिकायत वाद संख्या 79/2025 (पुराना नंबर 2626/2024) (रमाकांत मिश्रा बनाम स्नेहलता), धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना औंछा, जिला मैनपुरी के तहत पारित सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2024 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो वर्तमान में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 5, मैनपुरी की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच पैसे का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पैसे के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले 'दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.', जो 2010 (5) एससीसी 663 में रिपोर्ट किया गया है, पर भरोसा जताया है। संबंधित पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट—टैकलिंग एन एवेलांच ऑफ केसेस' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर/:

'...अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ दंड (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि यह धन का भुगतान सुनिश्चित करने का अधिक एक साधन है। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के लिए उपचार के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ दर्ज की गई उन शिकायतों की संख्या की जांच करें जो अंतिम निर्णय से पहले 'सुलह' या 'निस्तारित' हो गई, और दूसरी तरफ उन मामलों की जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा निस्तारित हो गया था और केवल एक बहुत छोटी संख्या में मामले जारी रहे।'

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गई उन आशंकाओं के लिए भी कुछ समर्थन है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा किया जा रहा है, हालांकि यह मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान होता है, जिससे न्याय वितरण में अनावश्यक देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में विलंब से शमन को चुनते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायावादी का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेते ही शमन का विकल्प चुनने के बजाय इसे अंतिम उपाय के रूप में चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का जोखिम लेने को तैयार रहते हैं और फिर समझौते का मार्ग तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि शमन चुनने में अनावश्यक देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटारा या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का सूचक है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान शमन का चुनाव करें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसा कोई वैध बचाव है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर कर सकता है और चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित अदालत इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकती है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान करेगी जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, अदालत विशेष रूप से 'दामोदर एस. प्रभु' (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगी।
6. यदि आवेदक अपराध के शमन के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना होगा और मुकदमे का सामना करना होगा, और अदालत कानून के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन पर निर्णय दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।
8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह आवेदन दिया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

18 मार्च, 2026

एस.के.डी.

(दीपक वर्मा, जे.)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।